



निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 20 पटना, बुधवार, 27 वैशाख 1939 (श0)  
17 मई 2017 (ई0)

### विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-2	भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---	भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि। ---	भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---	भाग-9—विज्ञापन ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। ---	भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण। ---	भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। ---
भाग-4—बिहार अधिनियम ---	पूरक ---
	पूरक-क 3-5

# भाग-1

## नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

24 अप्रैल 2017

सं० प्र०२/BSPHCL-विविध-29/2013(खण्ड)05—प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-1993, दिनांक 17.02.2017 द्वारा श्री श्याम किशोर झा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली (हाजीपुर) की सेवाएँ, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कं० लि०, पटना के अधीन साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०, के मगध डिवीजन के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर ऊर्जा विभाग को अगले आदेश तक सौंपी गई है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-135-141 में विनिर्दिष्ट अपराधों की सुनवाई हेतु, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के अधीन मगध डिवीजन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-153 (1) के अधीन गठित विशेष न्यायालय में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-153 (2) के अधीन श्री श्याम किशोर झा को प्रतिनियुक्ति के आधार पर अगले आदेश तक पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विनोदा नन्द झा, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 9—571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

# बिहार गजट

## का

## पूरक(अ0)

## प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं

9 मई 2017

सं0 ग्रा0वि0-14(को0)सु0-01/2017/309841-ग्रा0वि0—श्री शैलेश कुमार केसरी, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज (सुपौल) को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावा दल द्वारा दिनांक 11.01.2017 को 25,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने तथा उनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड सं0-002/2017 दर्ज होने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9(2)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-300917 दिनांक 20.02.2017 द्वारा कारा निरोध की तिथि 11.01.2017 से उनके कारावास की अवधि तक के लिए निलम्बित किया गया।

2. श्री शैलेश कुमार केसरी ने कारा से मुक्त होने के उपरान्त विभाग में अपना योगदान दिनांक 23.03.2017 को समर्पित किया है।

3. अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(3)(i) के आलोक में श्री केसरी को निलम्बनमुक्त करते हुए दिनांक 23.03.2017 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत किया जाता है।

4. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राधा किशोर झा, विशेष सचिव।

11 मई 2017

सं0-ग्रा0वि0-14(को0)सु0-01/2017/309877-ग्रा0वि0—श्री शैलेश कुमार केसरी, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज (सुपौल) को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावा दल द्वारा दिनांक 11.01.2017 को 25,000/- रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में

भेजने तथा निगरानी थाना कांड सं0-002/2017 दर्ज होने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 भाग-4 के नियम- 9(2)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में कारा निरोध की तिथि 11.01.2017 से उनके कारावास की अवधि तक के लिए विभागीय अधिसूचना सं0- 300917 दिनांक 20.02.2017 द्वारा निलम्बित किया गया।

2. श्री केसरी के द्वारा दिनांक 21.03.2017 को कारा से मुक्त होने के उपरान्त दिनांक 23.03.2017 को विभाग में अपना योगदान समर्पित किया गया। तत्पश्चात् विभागीय अधिसूचना सं0-309841 दिनांक 09.05.2017 द्वारा श्री केसरी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(3)(i) के आलोक में निलम्बनमुक्त कर योगदान स्वीकृत किया गया।

3. चूँकि श्री केसरी के विरुद्ध गंभीर कदाचार/भ्रष्टाचार का आरोप है तथा उन्हें रिश्वत लेते पकड़ा गया जिसके लिए उनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड सं0-002/2017 दर्ज है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्री केसरी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(ग) के आलोक में योगदान स्वीकृति की तिथि दिनांक 23.03.2017 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलम्बित किया जाता है।

4. निलम्बन अवधि में श्री केसरी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

5. निलम्बन अवधि में श्री केसरी का मुख्यालय ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

6. निलम्बनादेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राधा किशोर झा, विशेष सचिव।

सं० 6 / आ०-376 / 2006(खण्ड)सा०प्र०-5250  
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प  
2 मई 2017

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-1431 दिनांक 27.02.2017 द्वारा सूचित किया गया था कि श्री सुधीर कुमार, भा.प्र.से.(बिहार:1987), तत्कालीन अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के विरुद्ध बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित इण्टर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (प्रारम्भिक-2014) के प्रश्न-पत्र के परीक्षा पूर्व सार्वजनिक हो जाने के मामले में भा०द०वि० की धारा-419/420/467/468/ 471/34 एवं आई० टी० एक्ट की धारा-66/(डी.) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 की धारा-13(2) के तहत अगमकुओं थाना में आपराधिक कांड संख्या-44/2017 दिनांक 04.02.2017 दर्ज किया गया है। जो सम्प्रति अनुसंधानान्तर्गत है।

2. प्रासंगिक आपराधिक कृत्य में श्री सुधीर कुमार की संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के आधार पर दिनांक 24.02.2017 को उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में अग्रसारित किया गया तथा मामला अनुसंधानान्तर्गत होने के कारण राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत उन्हें अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-3 के उप-नियम 2 एवं उप-नियम 3 के प्रावधानों के तहत उन्हें हिरासत में लिये जाने की तिथि 24.02.2017 से विभागीय आदेश संख्या-2628 दिनांक 03.03.2017 के द्वारा निलंबित किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक 2856/गो० दिनांक 18.04.2017 द्वारा इनके विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव जांच प्रतिवेदन सहित प्राप्त है, जो अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है।

3. श्री सुधीर कुमार, भा0प्र0से0 (बिहार: 1987) सम्प्रति न्यायिक हिरासत में हैं।
4. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार के अधिसूचना दिनांक 21.12.2015 की कंडिका-2(iii) के आलोक में भारतीय प्रशासनिक सेवा के बिहार संवर्ग के श्री सुधीर कुमार, भा0प्र0से0 (बिहार: 1987) के निलंबन की प्रथम समीक्षा निलंबन समीक्षा समिति द्वारा दिनांक 21.04.2017 को की गई है। श्री कुमार के न्यायिक हिरासत में रहने एवं मामला अनुसंधानान्तर्गत होने की स्थिति में विचारोपरांत निलंबन को बरकरार रखने की अनुशंसा की गयी है।
5. अतः दिनांक 21.04.2017 को आयोजित निलंबन समीक्षा समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत श्री सुधीर कुमार, भा0प्र0से0 (बिहार: 1987) तत्कालीन अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को निलंबन में बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 9—571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>